

मुख्य समाचार”

- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा— विकसित भारत के सपने को साकार करने में कला व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
और
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप— प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, कांग्रेस के अपने ही लोग सरकार की कार्यशैली पर उठा रहे हैं सवाल।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में कला व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिमला में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेवा पर्व के अवसर पर आयोजित विकसित भारत के रंग कला के संग चित्रकला कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और जनधन जैसी अनेक योजनाओं ने राष्ट्र की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इस कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

सेवा पर्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष शृंखला — सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बना रही है और राष्ट्र को ज्ञान की महाशक्ति बनने में मदद कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले ग्यारह वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किया है। इस दौरान, भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेज़ी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा जैसी पहल शिक्षा के लचीलेपन, बहुविषयकता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है।

इस वर्ष 29 अप्रैल को नई दिल्ली में युगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रही है।

देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं।

सरकार के प्रयासों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51 हजार से बढ़कर इस वर्ष 70 हजार से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 6 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये वाहन घटना स्थल पर ही साक्ष्य जुटाने, उनका विश्लेषण करने और अपराधों की प्रारंभिक जांच को तेज व अधिक सटीक बनाने में पुलिस को महत्वपूर्ण सहयोग देंगे।

घटना घटती है तो उस घटना की सही साक्ष्य एकत्रित किए जाए। उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं। उस समय उनके डीएनए मोबाइल बैन के द्वारा हम जाकर चेक कर सकते हैं। इन मोबाइल वैनों का लेने का उद्देश्य है कि जहां भी घटना घटित हुई है वहीं से सैंपल को एकत्रित कर वहीं घटना की जानकारी को अपने पास लाने के बाद सही रूप से, उसको अमलीजामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया है और विपक्ष बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 15 सौ करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी पैंशनरों और एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के मुद्दे पर कहा कि अगले चार-पांच महीनों तक कर्मचारियों को सैलरी में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

जे.पी. नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने प्रदेश के दौरे के दौरान 3 अक्टूबर को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल करेंगे।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर फिजूलखर्ची को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनहित के लिए पैसों की कमी है, जबकि अधिकारियों, विधायकों व मंत्रियों के पास विदेशी दौरो के लिए पर्याप्त धन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कांग्रेस के अपने ही लोग सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 15 सौ करोड़ रूपए की सहायता राशि पर मुख्यमंत्री आभार जताने की बजाए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड प्रतिनिधिमंडल

न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में उच्चायुक्त पैट्रिक जॉन राटा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र में सहयोग से प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के सहयोग से प्रदेश आधुनिक सतत और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाकर सेब और नाशपति की खेती में एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी.एस.टी में भारी राहत दे रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार टैक्स का बोझ लादकर लोगों की परेशानियों में इज़ाफा कर रही है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की वस्तुओं पर जी.एस.टी कम करके प्रत्येक परिवार को हर महीने पांच हजार रूपए तक का लाभ पहुंचाया है।

तहबाजारी

रेहड़ी-फड़ी तह-बाजारी यूनियन ने सीटू के बेनर तले अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने नगर निगम शिमला पर गैर-कानूनी तरीके से तह-बाजारियों को उजाड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर-निगम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की अवहेलना कर रहा है।

जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वह कहता है कि जहां की जो जनसंख्या है, किसी भी जगह की, उसका लगभग ढाई पर्सेंट तक भी वो तहबाजारी में वो बस सकता है। वहां काम कर सकता है। तो शिमला की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो साढ़े सात हजार होने चाहिए थे यहां तहबाजारी, यहां तो हजार लोग भी नहीं हैं तहबाजारी। यह तर्कसंगत नहीं है, जो कानून है स्ट्रीट वेंडर्स कानून में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना तहबाजारी का काम करने का अधिकार है।

भाजपा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ज़मीन बचाओ—मकान बचाओ समिति का गठन किया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता व विधायक त्रिलोक जम्वाल को इस समिति का संयोजक, बिहारी लाल शर्मा को सचिव जबकि सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल व बलवीर वर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है।